(b) what action Government propose to take on each of them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) 33 applications received from the State of Kerala for grant of Letters of Intent for setting up of Industrial units are pending for clearance as on 30th June, 1991.

(b) The applications are at various stages of processing and decision regarding approvals will be taken in consultation with the concerned Administrative Ministries and technical authorities.

Slackness in industrial growth

384. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that industrial growth has slackened in the last one year;

(b) what is the expected industrial growth of last one year; and

(c) what was the target of industrial growth in last financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) to (c) According to the Index of Industrial Production compiled by CSO Central Statistical Organisation the overall rate of industrial growth was 8.4 per cent during 1990-91 which was almost at the same level as that achieved in the last financial year.

The Eighth Five Year Plan document is not yet finalised and as such, the yearly targeted rate of industrial growth is not available.

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

385. **डा. रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि हुई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) पिछले पंद्रह महीनों के दौरान ऐसी वृद्धि का महीना-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुदीन अहमद) : (क) और (ख) अप्रैल, 1990 से जून, 1991 तक (नवीनतम उपलब्ध) पिछले 15 महीनो के दौरान खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में आया माह-वार-प्रतिशत उतार-चढाव दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। (**देखिए**—परिशिष्ट 159, अनुपत्र 15) खाद्य तेलो के मूल्यो में वृद्धि के कारणों में खाद्य तेलों की मांग आपूर्ति मे अंतर होना, मुद्रा-पूर्ति मे वृद्धि होना तथा ढुलाई प्रभार मे बढोतरी होना शामिल है ।

(ग) सरकार ने खाद्य तेलो के मूल्यो में वृद्धि के रूख पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक उपाय किए है । इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) वनस्पति के विनिर्माण में विलायक (साल्वेंट) निष्कर्षित गैर-परम्परागत तेलो के प्रयोग करने पर उत्पाद-शुल्क की छूट देना ।

(2) खाद्य तेलो, जिनमें वनस्पति शामिल है, के विक्रेताओं/संसाधकों तथा विनिर्माताओं द्वारा रखे जाने वाले खाद्य तिलहनों तथा तेलों को स्टाक-सीमाओं में छूट दना/कमी करना ।

(3) राज्य सरकारों से, खाद्य तेलों और तिलहनों के जमाखोरों तथा कालाबाजारियो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद ऋण सीमाओं पर रोक लगाना ।